Off take of Foodgrains from Central Pool

1267. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the off take of foodgrains from the Central Pool declined in 1981 compared to that of previous year; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R.V. SWAMINATHAN) : (a) Yes, Sir. The off take from the Central Pool was about 11.85 million tonnes in 1981 as against 13.87 million tonnes in 1980.

(b) The scarcity and drought conditions during July, 1979-June, 1980 resulted in fall in production and consequently increased pressure on public distribution system. With increase in production during both Kharif and Rabi in 1980-81 the open market availability was better, resulting in lower off take in some States.

Production of Sugar

1268. SHRI TARIQ ANWAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether it is a fact that the production of sugar in the country has crossed the 18 lakh tonnes mark in the first three months of the sugar year 1981-82 beginning October, 1981 marking an increase of 4 lakh tonnes over the corresponding period in 1980-81 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : Yes, Sir. The sugar production in the first three months of the sugar year 1981-82, that is, upto 31st December, 1981 was 18.02 lakh tonnes as against the production of 13.99 lakh tonnes during the corresponding period of 1980-81 sugar year, showing an increase of about 4.03 lakh tonnes.

देश में सहकारी समितियों की कुल संख्या

1269. **श्री छोटे सिंह यादव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कुल कितनी सहकारी समितियां हैं;

(ख) प्रारम्भिक, केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अलग-अलग श्रम और ऋण-दाता समितियों सहित सभी प्रकार की कुल कितनी समितियां हैं;

(ग) इनमें से कुल कितनी समितियां निर्वाचित निदेशक बोर्डों द्वारा चलाई जा रही हैं और कितनी समितियां मनोनीत पदाधिकारियों/निदेशक बोर्ड और प्रशासकों द्वारा चलाई जा रही हैं; और

(घ) सरकार का विचार शीघ्र चुनाव कराकर इन समितियों का प्रशासन निर्वाचित पदाधिकारियों को कब तक सौंपने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 30 जून, 1980 को देश में 2,94,286 सहकारी समितियां थीं, जिनके बारे में केवल अस्थाई आंकड़े उपलब्ध हैं। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) उपलब्ध जानकारी विवरण-2 में दी गई है।

(ग) 30-6-1978 को अधिक्रमण/निलम्बन के अंतर्गत सहकारी समितियों की प्रबन्ध समितियों की संख्या के बारे में राज्य-वार स्थिति, जिसके नवीनतम प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं, विवरण-3 में दर्शायी गई हैं।

(घ) "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है तथा राज्यों में सहकारी समितियों की देखरेख करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। इन समितियों का नियंत्रण सम्बन्धित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम में सहकारी समितियों के पंजीयक को सुधारात्मक उपाय के रूप में तथा कुछ परिस्थितियों में सामान्य प्रशासनिक कार्यवाही के रूप में किसी भी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति को हटाने का अधिकार है। कुछ राज्यों में सहकारी समिति विधान में यह भी व्यवस्था है कि जहां पदमुक्त समिति समय पर प्रबन्ध समिति का चुनाव नहीं कराती वहां उक्त समिति समाप्त हो जाएगी तथा ऐसी समितियों में पंजीयक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अधिक्रमण की कुल अवधि भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग होती है और यह प्राय: चार वर्ष से अधिक नहीं होती।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से हटायी गई प्रबन्ध समितियों का शीघ्र चुनाव कराने तथा निर्वाचित पदाधिकारियों की प्रबन्ध समितियां बनाने के लिए अनुरोध किया है।

विवरण-1

30-6-1980 को सभी श्रेणियों की सहकारी समितियों की राज्यवार कुल संख्या।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	33044
2.	असम	6908
3.	बिहार	12390
4.	गुजरात	30168
5.	हरियाणा	5018
6.	हिमाचल प्रदेश	3487
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1737
8.	कर्नाटक	21662
9.	केरल	5983
10.	मध्य प्रदेश	11655
11.	महाराष्ट्र	57352
12.	मणिपुर	1437
13.	मेघालय	681
14.	नागालैण्ड	210
15.	उड़ीसा	6154
16.	पंजाब	16900
17.	राजस्थान	18275
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	13345
20.	त्रिपुरा	708
21.	उत्तर प्रदेश	20745
22.	प० बंगाल	22683
	संघ शासित क्षेत्र :	
23.	अंडमान एवं निकोबार	261
24.	अरूणाचल प्रदेश	104
25.	चण्डीगढ़	471
26.	दादरा एवं नागर हवेली	34
27.	दिल्ली	2239
28.	गोवा, दमन तथा दीव	432
29.	लक्षद्वीप	32
30.	मिजोरम	—
31.	पांडिचेरी	171
	अखिल भारत	294286

*राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किए गए अस्थायी आंकड़े।

विवरण-2

30-6-78 को राज्य, केन्द्रीय, जिला और प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियां।

समितियों की श्रेणी	30-6-78 को सहकारी समितियों की संख्या		
	कुल	ऋण	श्रम
राज्य	200	47	4
केन्द्रीय	938	345	—
जिला	778	—	78
प्राथमिक	2,98,552	1,43,232	10,492
योग :	3,00,441	1,43,624	10 534

स्रोत : भारत में सहकारी आन्दोलन के संबन्ध में सांख्यिकीय विवरण 1977-78 : भारतीय रिजर्व बैंक

विवरण-3

30-6-78 को सहकारी समितियों की प्रबन्धक समितियों के अधिक्रमण/निलम्बन के बारे में राज्यवार स्थिति।

राज्य/संघ शासित राज्य	अधिक्रमण/निलम्बन के अंतर्गत समितियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	570
गुजरात	337
हरियाणा*	2423
हिमाचल प्रदेश	19
जम्मू तथा कश्मीर**	146
कर्नाटक	575
केरल*	79
मध्य प्रदेश	4662
महाराष्ट्र	795
मणिपुर	524
उड़ीसा	586
पंजाब	299
राजस्थान	427
तमिलनाडु*	570
त्रिपुरा	13
उत्तर प्रदेश*	2629
प० बंगाल	149
चण्डीगढ़**	2
दादर तथा नागर हवेली	4
गोवा, दमन तथा दीव	13
लक्षद्वीप	7
पांडिचेरी	17
योग	14,846

*ये आंकड़े 1976-77 के सम्बन्ध में हैं।

**रिपोर्ट देने वाले प्राधिकारियों के संबन्ध में आंकड़े।

***रिपोर्ट देने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में आंकड़े।

स्रोत : भारत में सहकारी आंदोलन के संबन्ध में साख्यिकीय विवरण, 1977-78। (भाग-2)
भारतीय रिजर्व बैंक

Cancellation of Sugar Licences in Delhi Cantt. Area

1270. SHRI SHIBU SOREN : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not cancelled the whole-sale sugar licences of whole-sale dealers of Delhi Cantonment area, who did not sell and purchase the sugar in the stipulated period of 1st January, 1981 to June, 1981 and became active only when sugar became scarce and yielded undue profit, while the licences of other dealers were cancelled; and

(b) if so, the details and reasons alongwith the name and addresses of such dealers whose licences were not cancelled?